

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 02 जुलाई 2025, समय 1305 (5 मिनट))

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में साढ़े तीन करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1 करोड़ 92 लाख लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। इस योजना का लाभ इस वर्ष पहली अगस्त से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पर आने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन 15 हजार रुपये तक मिलेगा। उन्होंने बताया -

उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दो साल तक की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश के खेल परिदृश्य को बदलने और नागरिकों को खेल गतिविधियों से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नीति लागू होने से दुनिया के शीर्ष पांच खेल राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह नीति खेल पर्यटन को बढ़ावा देने और देश में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को आकर्षित करने में भी मदद करेगी।

हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 21 दिनों से चला आ रहा छात्र आंदोलन कल रात समाप्त हो गया। प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद छात्रों ने कल देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया। नलवा से भाजपा विधायक रणधीर पनिहार ने पत्रकारवार्ता में बताया कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत के जरिए इस गतिरोध को दूर करने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों से बातचीत के लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के नेतृत्व में एक

समिति का भी गठन किया था। समिति के सामने विद्यार्थियों ने अपनी आठ मांगें रखी थी जिन्हें मान लिया गया है –

2- रणधीर पनिहार-31 सेकंड

उन्होंने कहा कि सात मांगों पर तुरंत कार्रवाई की गई है और एक मांग है जिसकी जांच कर समय अनुसार पूरा किया जाएगा। जांच के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी जो मांगें स्वीकार की गई हैं उनमें प्रोफेसर व विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है

फरीदाबाद में आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय में कल 8वां वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया गया। यह दिन भारत के आर्थिक इतिहास में “एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार” की सोच को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक पड़ाव माना जाता है। इस अवसर पर सहायक आयुक्त जीएसटी, अरविंदर सिंह ने कहा कि जीएसटी से देश के आर्थिक एकीकरण और विकास में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। इसने कर प्रणाली को सरल बनाकर व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था और कुशल कर प्रबंधन का प्रतीक है। संयुक्त आयुक्त, अपील, दीपिका चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा का प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह 47 हजार 82 रुपये से अधिक रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डिजिटल इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण किया है, जिससे भारत एक वैश्विक डिजिटल शक्ति बन गया है। डिजिटल इंडिया के दस वर्ष पूरे होने पर, श्री शाह ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य सभी क्षेत्र इससे सशक्त बने हैं।
